

नए भारत के निर्माण में मेक इन इण्डिया का योगदान

डॉ.पंकज मिश्र

(विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय)
संत तुलसीदास पी0जी0 कालेज,
कादीपुर-सुलतानपुर, उ0प्र0।

प्रस्तावना: - आजादी के बाद से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्चस्तरीय तरक्की करके एक नये आयाम पर पहुचने के लिए सफलतापूर्वक प्रयासरत रहा है। भारत वर्ष अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए विकास की नई दिशा तलाश कर रहा है और सफलतम इतिहास की रचना करने में कामयाब हो रहा है। किसी भी देश के विकास के पहलू को देखा जाय तो उसके कई आयाम होते हैं जिसके माध्यम से वह अपना कार्य सम्पन्न करता है। देशों को समयानुसार अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करके नयी-नयी विधियों को अपनाना पड़ता है सुधारात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है और साथ ही साथ देश की राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़कर सभी को नये-नये नियमों एवं कानूनों में योगदान करके नवीनतम बातों को अपना कर देश को नयी दिशा-दशा एवं गति देना एक आवश्यक कदम होता है। भारत वर्ष में लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस के शासनकाल में बनी विभिन्न योजनाओं ने अपना कार्य किया परन्तु समय के साथ देश को भ्रष्टाचार एवं मंहगाई विदेशी उत्पादन पर निर्भरता जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए देश की जनता ने सन् 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे नरेन्द्र दामोदरदास मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना यही से शुरू होता है भारत के निर्माण का कुछ परिकल्प जिसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितम्बर 2014 को मेक-इन-इण्डिया कार्यक्रम की स्थापना करके किया।

मेक-इन-इण्डिया कार्यक्रम-

25 सितम्बर 2014 को इस योजना का शुभारम्भ किया गया जिसका लक्ष्य रखा गया कि देश का विनिर्माण क्षेत्र सफल हो क्योंकि जब तक निर्माण कार्य देश में नहीं होगा देश का कुशल एवं चैमुखी विकास करना सम्भव नहीं होगा और देश की मुद्रा विदेशों में जाती ही रहेगी और देश का विदेशी उत्पादन मूल्य एवं उन पर आश्रितता बनी रहेगी। देश में रोजगार निम्न अवस्था में रहेगा और देश हमेशा मजबूरी की दशा में ही रहेगा इन्ही सब विषयों को ध्यान में रखकर इस योजना की आधार शिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी। मेक-इन-इण्डिया कार्यक्रम देश की उद्यमशीलता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे भारतीय पूँजीपतियों और युवाओं में उद्यमिता की भावना का विकास होगा जिससे देश में कुशल रोजगार की दशाएं नागरिकों के समक्ष उत्पन्न होगी।

मेक-इन-इण्डिया कार्यक्रम का मुख्य आधार विनिर्माण क्षेत्र होने के कारण इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ाते हुए निवेश के लिए ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है कि आधुनिक एवं कुशल संरचना बुनियादी सुविधा एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में आसानी से उपलब्ध हो सके जिससे नये सशक्त भारत का निर्माण सम्भव हो सके सरकार का यह प्रयास रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र (उद्योग) एवं सरकारों के बीच एक सेतु का निर्माण हो सके जिससे सरकार उत्पादन का माहौल

देश में उपलब्ध कराए एवं देश का उद्यमी उसका सकारात्मक लाभ उठाकर देश के नागरिकों को रोजगार का नया आयाम दे सके। भारत द्वारा मेक-इन-इण्डिया कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जापान, फ्रांस, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने निवेश हेतु अपना उत्साहबर्धक समर्थन दिखाया है। ये सभी बड़े उत्पादक देश हैं जो भारत में आकर निर्माण कार्य सम्पन्न कर अपनी टेक्नोलॉजी को भारत में साझा करने का मन बनाया है।

मेक-इन-इण्डिया का लक्ष्य:-

भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना के समय कुछ प्रमुख लक्ष्यों को केन्द्रित किया है जो इस प्रकार हैं।

- 1^o इस योजना के तहत अभियान चलाकर सरकार ने प्राथमिकता वाले 25 क्षेत्रों का अवलोकन किया जिनको प्रोत्साहन देने की योजना बनी।
- 2^o विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 12% से 14% तक प्रतिवर्ष के स्तर पर ले जाना।
- 3^o देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में वर्ष 2022 तक 16% से 25% तक की वृद्धि करना है।
- 4^o केवल विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन का रोजगार वर्ष 2022 तक उत्पन्न करना।
- 5^o भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्वप्रतिस्पर्धी बनाना।
- 6^o सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण प्रवासी एवं शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल का निर्माण एवं विकास करना।
- 7^o मूल्य सम्बर्द्धन प्रणाली और निर्माण की तकनीकी कमियों को हमेशा के लिए दूर करना।
- 8^o भारतीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना एवं ख्याति में वृद्धि करना।
- 9^o भारतीय क्षेत्रीयता की पहचान विश्व को विनिर्माण के हब के रूप में कराना।
- 10^o स्थानीय क्षेत्र में उत्पादन क्रिया कलापो की स्थापना करके कुशल रोजगार प्रदान करना एवं स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना।
- 11^o विदेशी तकनीकी प्रणाली को भारत में लाना एवं भारतीय उत्पाद को विश्व प्रतिस्पर्धी बनाकर उनका निर्यात सम्बर्द्धन करना।

नये भारत के निर्माण में मेक-इन-इण्डिया की चुनौतियाँ:-

भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी द्वारा लाया गया यह अभियान अपने आप में एक क्रान्तिकारी विचार है परन्तु इसे पूर्णता से कर पाना इतना आसान कार्य नहीं है भारतीय विभिन्न विविधताओं को देखते हुए इसके पूर्ण होने की सम्भावना को निम्न विशिष्ट चुनौतियों को पूर्ण करना होगा।

1^० निर्यात बढ़ाने की चुनौती - भारत के इस प्रोग्राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत में निर्मित (मेक-इन-इण्डिया) का माल विश्व के अन्य देशों के माँग के अनुरूप बनाना है जिससे वे अपना स्थान विदेशों में बनाकर माँग को बनाए रखें। यह एक प्रमुख चुनौती देश के समक्ष होगी। क्योंकि बिना निर्यात के विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो सकती और योजना का सफल संचालन नहीं हो सकता है।

2^० प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने की समस्या:-

भारत की इस महत्वाकांक्षी योजना में एक समस्या यह रही कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्राप्ति जबकि सरकार द्वारा इसके लिए अच्छे प्रयास किये जा रहे हैं जिसके लिए रक्षाक्षेत्र नीति को उदार करते हुए थ्रूफण्ड को 26% से बढ़ाकर 49% तक लाया गया साथ-साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए रक्षा क्षेत्र थ्रूफण्ड को 100% तक मंजूर कर दी गयी साथ-साथ वीक एवं चिकित्सा सम्बन्धी मामलों में व्यवस्था को उदारतम स्तर पर लाया गया इसके लिए निवेश एक चुनौती का कार्य है कि योजना के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति हो।

3^० निवेशको सम्बन्धी समस्याएँ:-

मेक-इन-इण्डिया कार्यक्रम में निवेशक निवेश से पहले अपने लिए अनुकूल विभिन्न मापदण्डों की जांच-परख करके अपने अनुकूल परिस्थिति पाने पर ही निवेश करेगा वह विभिन्न प्रकार की दशाओं का पर्याप्त ध्यान रखेगा जैसे-

- 1^० कच्चे माल की आपूर्ति दशाएँ-किस स्तर की है।
- 2^० श्रम बल की प्राप्ति एवं प्रयोग दर क्या है वह भविष्य में कैसी रह सकती है ।
- 3^० उत्पादन के वातावरण की संरचनात्मक व्यवस्था किस प्रकार की है।
- 4^० सुरक्षा परिवहन संदेशवाहन की दशाएँ किस अवस्था की है।
- 5^० राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रकृति स्थायी है या परिवर्तनशील।
- 6^० उत्पादन नियमों कानूनों पर गहन विचार विमर्श
- 7^० कार्यवाही योजना की प्रकृति के साथ भविष्य की आशा
- 8^० टेम्पलमार्क पेटेंट आदि का पंजीकरण एवं प्रयोग की दशाएँ।

9^१ आपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया प्राणाली नीति।

10^१ समस्यात्मक कार्यवाही की निवारण प्रक्रिया।

निष्कर्ष एवं सुझाव:-

भारत सरकार द्वारा स्थापित मेक-इन-इण्डिया प्रोग्राम देश के लिए किसी क्रान्तिकारी परिवर्तनशील विचार से कम नहीं है इसके माध्यम से भारत सरकार की सबसे बड़ी सोच नवाचार को बढ़ाकर देश में उद्यमशीलता को उस स्तर पर ले जाना है जहां पर रोजगार मेकर बनकर देश एवं विभिन्न देशों के कुशल व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है तथा साथ में बाहरी देशों के आयातों को कम करके उनकी टेक्नोलॉजी को देश में प्राप्त करके वैश्विक स्तर के माल का निर्माण करना देश का लक्ष्य है। वर्तमान समय में मेक-इन-इण्डिया प्रोग्राम से निर्मित विभिन्न सामानों की मांग विभिन्न देश में हो रही है। उत्तर-प्रदेश के अमेठी जिले में सेना के प्रयोग हेतु असाइट 203 राइफल तथा भारतीय कम्पनी द्वारा निर्मित जूते बुलट प्रूफ जैकेट की मांग बढ़ रही है इस योजना को सरकारी एवं निवेशकतंत्र ठीक से मिलकर संचालित करे तो यह योजना भारत वर्ष के आर्थिक विकास उद्यमशीलताए वस्तु उत्पादन एवं रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वर्तमान समय में कोई भी योजना विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना करती है परन्तु सुधार कार्यक्रम को अपना कर यह योजना एक दिन भारत की शक्ति का लोहा विश्व में मनवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

संदर्भ:- 1^१ मेक-इन-इण्डिया प्रोग्राम लिंक्स।

2^१ लाइव परियोजना विशेषांक 2018।

3^१ सरकारी नीतिया।

4^१ रूपांकपणहवअणपद

, , , , ,